nwda.gov.in

तय होगी जल उपयोग दक्षता की एक समान परिभाषा

मनीष तिवारी • नई दिल्ली

- कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी के उपयोग की क्षमता बढ़ाने के लिए उप समूहों का गठन
- जल उपयोग दक्षता का पैमाना तय करने के साथ ही लीकेज व नुकसान रोकने का तरीका भी बताएंगे

बहुमूल्य जल की बर्बादी रोकने और उसके उपयोग की दक्षता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित एक टास्क फोर्स ने कृषि, उद्योग जगत और शहरी-ग्रामीण घरों में इसके प्रयोग को लेकर अलग-अलग रूपरेखा बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए तीन उपसमूहों का गठन किया गया है, जो इन क्षेत्रों में पानी के इस्तेमाल के नियम-कायदे तय करने के संदर्भ में अपनी सिफारिशें करेगा। उपसमूहों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जल उपयोग दक्षता (डब्लूयूई) की एकसमान परिभाषा तय करना है।

जलशक्ति मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय जल मिशन के तहत कार्य कर रहे ब्यूरो आफ वाटर यूज इफीशिएंसी (बीडब्ल्यूयूई) के राष्ट्रीय कार्यबल देश में पानी के इस्तेमाल को लेकर विस्तृत फ्रेमवर्क बनाना चाहता है। यह कार्यबल पानी के इस्तेमाल की मौजूदा क्षमता में 20 प्रतिशत सुधार के मुख्य उद्देश्य के साथ काम कर रहा है।

देश में पानी का सबसे अधिक इस्तेमाल सिंचाई में होता है, लेकिन यहां पानी के प्रयोग की दक्षता नापने

के अलग-अलग पैमाने हैं, जैसे फसल में उपयोग किए जाने वाले पानी से लेकर प्रति इकाई जीडीपी में योगदान तक। इसी तरह घरेलू तथा उद्योगों में पानी के उपयोग की दक्षता तय करने का कोई एक पैमाना नहीं है। विशेषज्ञों का भी कहना है कि पानी के इस्तेमाल को लेकर अभी तक कोई कुशल तरीका नहीं बन पाया है। इससे एक तो उपलब्ध जल का समुचित इस्तेमाल नहीं हो पाता और दूसरे, एक बहुमूल्य संसाधन की बर्बादी का सिलसिला भी कायम है। सिंचाई में लगभग 80 प्रतिशत जल का प्रयोग होता है, लेकिन इससे संबंधित परियोजनाओं में पानी के उचित-अनुचित इस्तेमाल को मापने का कोई प्रभावी तंत्र नहीं है। उपसमूहों के सामने उस पैमाने को तय करने की भी चुनौती है, जिसके जरिये जल उपयोग दक्षता का आकलन किया जाएगा। उपसमूह जल उपयोग के बुनियादी परिदृश्य को तय करेंगे, मसलन इसके निर्धारण की तकनीक, तरीका, निगरानी के संकेतक और अल्पावधि तथा दीर्घकालिक उपाय। सूत्रों के अनुसार, उपसमूहों को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वे जनजागरूकता और लोगों तक पहुंचने के कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के उपाय बताएं। इसी तरह एक अन्य चुनौती लीकेज और पानी के नुकसान को रोकने की भी है, जो हर दिन सभी जगह दिखाई देता है।

सिंचाई के लिए बने उपसमूह की अध्यक्षता गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के एमके सिन्हा करेंगे, जबकि उद्योगों के लिए गठित उपसमूह की अध्यक्षता इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजय राय करेंगे। शहरी और ग्रामीण इलाकों में घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी के बारे में रिपोर्ट सीआइआइ के कार्यकारी निदेशक कपिल कुमार नरूला प्रस्तुत करेंगे।